माननीय न्यायाधीश श्री *सुधीर मित्तल* जी के समक्ष

अनिल चाना- *याचिकाकर्ता*

बनाम

मेसर्स ज्ञानी राम रुलिया राम-*प्रतिवादी*

2018 की सीआरएम-एम संख्या 36869 और संबंधित मामले (132 मामले)

अक्टूबर 30, 2018

A) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 138 और 141 - पूर्व निदेशक दायित्व - याचिकाकर्ता ने विवाद फार्म संख्या 32 में चेक जारी करने से बहुत पहले इस्तीफा दे दिया और रिकॉर्ड पर कंपनी की वार्षिक विवरणी और इनकार नहीं किया - याचिकाकर्ता को बुलाने में मजिस्ट्रेट न्यायसंगत नहीं - अभियुक्त को बुलाना - न्यायालय को उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर संतुष्ट होना चाहिए कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त ने अपराध किया है - अनुपालन और सम्मन आदेश रद्द कर दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता पर प्रत्यावर्ती दायित्व लगाने के लिए, कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, कंपनी के व्यवसाय के संचालन में उसकी भूमिका के बारे में शिकायत में विशिष्ट कथन करना आवश्यक था। इस मामले में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता को समन करने में न्यायसंगत नहीं था। किसी अभियुक्त व्यक्ति को तलब करने के चरण में, ट्रायल कोर्ट/मजिस्ट्रेट को उसके समक्ष पेश की गई सामग्री के आधार पर संतुष्ट होना चाहिए कि प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों ने अपराध किया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने उत्तर के माध्यम से संदर्भित सामग्री को इस स्तर पर नहीं देखा जा सकता है क्योंकि शिकायत में इसका उल्लेख या भरोसा नहीं किया गया है।

(पैरा 21)

B) निदेशक पर दायित्व का बन्धन - ट्रायल कोर्ट शिकायतकर्ता को उन व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए कंपनी द्वारा दायर फॉर्म 32 और वार्षिक रिटर्न की प्रति पेश करने का निर्देश देगा, जो अपराध की तारीख को निदेशक थे।

और रूप कि ऐसे मामलों में जहां आरोपी-निदेशक अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक या चेक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं, उन्हें कंपनी के मामलों के संचालन में उनकी भूमिका के बारे में बिना किसी कथन के बुलाया जा सकता है। कंपनी के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी को बुलाने के लिए कंपनी के कारोबार के संचालन में उनकी भूमिका के बारे में आवश्यक कथन पर जोर दिया जाना चाहिए। पूर्णकालिक निदेशकों के संबंध में, अधिनियम की धारा 141 के शब्दों को केवल पुन: प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

(पैरा 29)

आरएस राय, कुणाल डावर, एडवोकेट के साथ सीनियर एडवोकेट; जसदीप सिंह गिल, एडवोकेट; गौतम दत्त, एडवोकेट; अभिनव सूद, एडवोकेट; आशीष गुप्ता, एडवोकेट; राजीव आनंद, एडवोकेट; याचिकाकर्ता की वकील अमनप्रीत कौर सभरवाल।

अरुण बंसल, एडवोकेट विद गौरव अग्रवाल, एडवोकेट;

आशीष यादव, अतिरिक्त एजी हरियाणा; प्रतिवादी (ओं) के लिए।

सुधीर मित्तल, जे.

1. यह निर्णय उपरोक्त 132 याचिकाओं का निपटारा करेगा क्योंकि उसमें तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं। सीआरएम-एम-36869-2018 से तथ्य निकाले जा रहे हैं जो ***अनिल चानना** बनाम **मेसर्स ज्ञानी राम रुलिया राम*** **के रूप में झुका हुआ है।**

2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 138 के तहत मेसर्स ज्ञानी राम रुलिया राम ***बनाम** अमीरा प्योर फूड प्राइवेट लिमिटेड* **के नाम से एक शिकायत संख्या *2597/2017* दिनांक *04.10.2017*** दायर की गई थी। सम तिथि के आदेश के तहत, उसमें उल्लिखित अभियुक्त व्यक्तियों (प्रतिवादी) को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता का नाम उत्तरदाताओं की सूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेख मिलता है। शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें प्रतिवादी अध्यक्ष और संबंधित निदेशकों के माध्यम से 'अमीरा

प्योर फूड प्राइवेट लिमिटेड' हैं। याचिकाकर्ता को कथित तौर पर निदेशक होने का भी आरोप लगाया गया है। विवादित चेक रिकॉर्ड पर अनुबंध पी-2 है। इसे अमीरा प्योर फूड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा तैयार किया गया है।

3. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका शिकायत को रद्द करने और इस आधार पर तलब करने के आदेश के लिए दायर की गई है कि याचिकाकर्ता 10.02.2006 से कंपनी का निदेशक नहीं रह गया है। यह तर्क दिया गया है कि यह तथ्य कंपनी मामलों के विभाग को प्रस्तुत फॉर्म नंबर 32 दिनांक 23.02.2006 में निहित है। यह आगे कंपनी के वार्षिक रिटर्न (अनुलग्नक पी -5 के रूप में संलग्न) में पुष्टि पाता है, जिसमें निदेशक/प्रबंधक/सचिव की सूची में, यह दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता 10.02.2006 से निदेशक नहीं रहा। उक्त दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 (2) के अनुसार शब्द के अर्थ के भीतर 'सार्वजनिक दस्तावेज' हैं। विवादित चेक 26.04.2017 का है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता चेक जारी करने की तारीख को कंपनी में निदेशक नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को कभी भी "कंपनी के मामलों के प्रभारी व्यक्ति या उसके व्यवसाय के लिए जिम्मेदार" के रूप में उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि शिकायत में उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है कि वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए किस तरह जिम्मेदार था। इस प्रकार, शिकायत दर्ज करना और सम्मन आदेश जारी करना, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और वे याचिकाकर्ता के खिलाफ रद्द किए जाने के योग्य हैं।

4. शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा याचिका का विरोध किया गया है। उसकी ओर से विस्तृत जवाब दाखिल किया गया है। यह पाया गया है कि कंपनी ने निर्यात उद्देश्यों के लिए हरियाणा राज्य में बड़ी संख्या में मंडियों से चावल खरीदा है। वही क्रेडिट पर खरीदा गया था। खरीदे गए उत्पाद के लिए भुगतान करने की देयता के निर्वहन में चेक जारी किए गए थे, लेकिन चेक अस्वीकृत हो गए थे। चूंकि, चेक बेईमानी के इरादे से जारी किए गए थे, इसलिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 406, 420 के तहत विभिन्न एफआईआर भी दर्ज की गई। तत्पश्चात्, कंपनी और इसके निदेशकों (पूर्व निदेशकों सहित) ने ऋणदाताओं के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और देय राशियों का भुगतान किया। नारनौल, सफीदों और गोहाना मंडियों के कमीशन एजेंटों के साथ किए गए समळौता ळ्ापान को रिकार्ड में रखा गया है। मतलोडा मंडी में 453 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। उत्तर के साथ विभिन्न मंडियों के कमीशन एजेंटों के साथ हुए समझौतों की एक सूची भी संलग्न की गई है। इस प्रकार, प्रस्तुत किया गया है, कि याचिकाकर्ता समझौता ज्ञापन का पक्षकार होने के नाते, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था। यद्यपि वह निदेशक नहीं रह गया था, वह कंपनी के कारोबार में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था और अधिनियम की धारा 141 के संदर्भ में उत्तरदायी था। शिकायत में कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के तरीके के बारे में कोई विशिष्ट कथन आवश्यक नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से सम्मन के आदेश को चुनौती दे सकता है।

5. मैं पहले शिकायतकर्ता-प्रतिवादी की ओर से उठाई गई अंतिम आपत्ति को लेने का इरादा रखता हूं। यह वर्तमान याचिका की विचारणीयता के संबंध में है। तर्क यह है कि सम्मन आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जारी किया गया है। इस तरह के आदेश के खिलाफ, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद सीआरपीसी के रूप में संदर्भित) की धारा 397 के तहत एक संशोधन को प्राथमिकता दी जा सकती थी। यह तर्क मुझे इस कारण से प्रभावित नहीं करता है कि वर्तमान याचिका शिकायत के साथ-साथ सम्मन आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है। पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच करने के लिए और अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की नियमितता की जांच करने के उद्देश्य से भी मामले के रिकॉर्ड को बुला सकता है। यह एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने की शक्ति के साथ निहित नहीं है। यह शक्ति केवल उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उपलब्ध है, जहां उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार, इस याचिका में की गई प्रार्थना को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पास पहली बार में सत्र न्यायालय के समक्ष एक वैकल्पिक उपाय था। इस प्रकार, तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

6. याचिकाकर्ता, कंपनी के अध्यक्ष और निदेशकों के खिलाफ आरोप इस प्रकार है: -

XXX XXX XXX

2. उपरोक्त नोटिस के आरोपी कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक हैं, अर्थात् अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड विल हरसरू गादी, 21 माइल स्टोन, पट्टौडी रोड, जिला। गुड़गांव हरियाणा और धान की फसलों और चावल की खरीद और निर्यात के व्यवसाय में काम करता है। अभियुक्त सभी आरोपी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रभारी हैं और आरोपी के रूप में कंपनी के सभी कार्यों और आचरण के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं, सभी कंपनी के सभी मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

XXX XXX XXX

7. 'कंपनियों द्वारा अपराध' से संबंधित अधिनियम की धारा 141 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"141. कंपनियों द्वारा अपराध। —

(1) यदि धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिये उस कम्पनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, साथ ही साथ वह कम्पनी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होगा:

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को दण्ड के भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता का प्रयोग किया था।

परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वित्तीय निगम में कोई पद या नियोजन धारण करने के आधार पर किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नामनिर्देशित किया जाता है, वहां वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, ऐसे निदेशक की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण है, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(अ)"कंपनी" का अर्थ है कोई भी निकाय कॉर्पोरेट और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

(आ) "निदेशक", एक फर्म के संबंध में, फर्म में एक भागीदार का मतलब है।

8. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, कंपनी के अलावा परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। ऐसा व्यक्ति 'निदेशक' के अलावा कोई और भी हो सकता है जब तक कि वह कंपनी का अधिकारी है। हालांकि, एक पदेन निदेशक उत्तरदायी नहीं है। यहां तक कि एक निदेशक भी मुकदमे के दौरान अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। निदेशक की निर्दोषता अथवा कंपनी के किसी अधिकारी, जो निदेशक नहीं है, की दोषीता से संबंधित प्रश्न साक्ष्य का विषय है।

9. इसलिए, सवाल एक ऐसे व्यक्ति के दायित्व के बारे में है जो 10.02.2006 से निदेशक नहीं रह गया है और जिसके खिलाफ शिकायत में कोई विशिष्ट कथन नहीं किया गया है कि वह किस तरीके से कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार था। ऊपर पुन: प्रस्तुत शिकायत के पैराग्राफ में, केवल यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता अन्य निदेशकों के साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, जो अधिनियम की धारा 141 के शब्दों का मात्र पुनरुत्पादन है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह स्थापित कानून है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा सम्मन आदेश जारी करने से पहले, उसे *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट महसूस करना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को तलब किया जा रहा है, उन्होंने अपराध किया है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता चेक जारी होने से बहुत पहले कंपनी में निदेशक नहीं रह गया था और एक पूर्व निदेशक होने के नाते, उसे उत्तरदायी बनाने के लिए, शिकायत में उस तरीके के बारे में बताना आवश्यक था जिसमें वह कंपनी के मामलों का प्रभारी था, लेकिन याचिकाकर्ता की भागीदारी के बारे में कोई विशिष्ट कथन नहीं था, शिकायत में

कहा गया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री थी कि *प्रथम दृष्टया* याचिकाकर्ता ने कोई अपराध किया था। उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को तलब करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और शिकायत और सम्मन आदेश रद्द करने योग्य है। हर्षेन्द्र कुमार डी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। ***बनाम*** *रेबतिलता कोले* ***और अन्य, श्रीमती अनीता मल्होत्रा*** [1] ***बनाम परिधान निर्यात संवर्धन परिषद*** *और अन्य, पूजा रविंदर देवीदासानी* ***बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य***[2]***, अशोक मल बाफना*** [3]***बनाम*** *मैसर्स अपर इंडिया स्टील एमएफजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड।* [4] ***और निर्णय दिनांक 28.04.2018 सीआरएल अपील संख्या 586-594/2018 अजय अग्रवाल*** *बनाम* ***मेसर्स इंटीग्रेटेड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड*** में पारित किया गया।सुदीप जैन ***बनाम*** *मेसर्स ईसीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआरएलएमसी संख्या 1821/* ***2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है,*** जिसका फैसला 06.05.2013 को हुआ था।

11. में ***हर्षेंद्र कुमार डी.*** *(सुप्रा)* के मामले में, तथ्य यह थे कि अभियुक्त-कंपनी ने कुछ चेक जारी किए थे, जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतें दर्ज की गईं और यह माना गया कि अपीलकर्ता सहित आरोपी कंपनी के प्रबंध निदेशक और दो निदेशक इसके दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार थे। समन जारी होने पर, अपीलकर्ता ने शिकायत और सम्मन आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उसने चेक जारी करने की तारीख से एक महीने से अधिक समय पहले निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था और यह तथ्य आरोपी-कंपनी द्वारा दायर फॉर्म नंबर 32 में दर्ज है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आरोपी कंपनी के निदेशक द्वारा इस्तीफा मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष में विचार का विषय है। उच्चतम न्यायालय ने सांविधिक उपबंधों का उल्लेख करने के बाद ***एस.एम.एस. फार्मास्युटिकल लिमिटेड*** *मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का उल्लेख किया।(* ***ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीता भल्ला***[5] और विभिन्न अन्य मामलों में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय दिया था और माना था कि फॉर्म संख्या 32 जैसे दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रकृति के हैं और संदेह से परे हैं और *प्रथम दृष्टया* चरण में देखे जा सकते हैं और अधिनियम की धारा 138 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया था।

12. अनीता मल्होत्रा ***(सुप्रा)*** *मामले में*, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने 31.08.1999 से अभियुक्त-कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था और यह जानकारी वैधानिक फॉर्म नंबर 32 के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई थी। अधिनियम की धारा 138 के तहत नोटिस दिनांक 10.12.2004 को दिया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया था। उसे निचली अदालत ने तलब किया था। समन आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका और शिकायत को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ***हर्षेंद्र कुमार डी.*** *(सुप्रा) और* अन्य मामलों में और माना गया कि कंपनियों द्वारा दायर फॉर्म नंबर 32 और वार्षिक रिटर्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 (2) के संदर्भ में सार्वजनिक दस्तावेज थे और ऐसे दस्तावेजों को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के प्रयोजनों के लिए देखा जा सकता है। फिर से, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया।

13. पूजा रविंदर देवीदासानी ***(सुप्रा)*** *में* तथ्य पहले के दो मामलों के समान थे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने चेक जारी करने की तारीख से पहले इस्तीफा दे दिया था और यह जानकारी फॉर्म नंबर 32 के माध्यम से कंपनियों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई थी और यह वार्षिक रिटर्न में भी निहित थी। फिर से यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था, कि फॉर्म नंबर 32 और कंपनी के वार्षिक रिटर्न जैसे दस्तावेज को यह पता लगाने के लिए देखा जा सकता है कि क्या एक आरोपी व्यक्ति अपराध के कमीशन की तारीख को कंपनी में निदेशक था और यहां तक कि अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए एक निदेशक को उत्तरदायी बनाने के लिए भी, उसके खिलाफ विशिष्ट कथन होना चाहिए जिसमें यह दिखाया गया हो कि वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए किस तरह जिम्मेदार था।

---

[1] 2011(1) आरसीआर (सीआरएल) 887

[2] 2011(4) आरसीआर (सीआरएल) 835

[3] 2015(1) आरसीआर (सा.रा.) 271

[4] 2017(3)सीआरएल सीसी 848

[5] 2005(4) आरसीआर (सीआरएल) 141

14. अशोक मल बाफना ***(सुप्रा)*** *मामले* में अपीलकर्ता आरोपी कंपनी में निदेशक था, जब चेक जारी किया गया था। हालांकि, चेक की वैधता की अवधि के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बाद, चेक को बदल दिया गया और प्रस्तुत किया गया। लेकिन, तब तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। यह माना गया कि उनके इस्तीफे के बाद, अपीलकर्ता ने आरोपी-कंपनी की गतिविधि में कोई भूमिका निभाना बंद कर दिया था और इस प्रकार, उसे उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था।

15. अजय अग्रवाल ***(सुप्रा) में*** *अनीता मल्होत्रा* (सुप्रा) *के फैसले* पर भरोसा किया गया है और उसका पालन किया गया है।

16. शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने गनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ***में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मजबूत भरोसा किया है।*** *(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनु मेहता और अन्य बनाम* ***स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक*** [6] बनाम ***महाराष्ट्र राज्य और अन्य आदि के मामले में भारत सरकार के*** *विरुद्ध मामले* ***की जांच की है।***[7]का उपयोग कर सकते हैं

17. इन ***गनमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड*** *(सुप्रा)* उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 138 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि अधिनियम की धारा 141 के शब्दों का पुनरुत्पादन, एक निदेशक को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है और जिस तरीके से वह कंपनी के मामलों का संचालन कर रहा था, उसे विशेष रूप से टाल दिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस फैसले को चुनौती दी और तर्क दिया कि कंपनी के मामलों के संचालन में एक व्यक्तिगत निदेशक द्वारा निभाई गई भूमिका एक आंतरिक मुद्दा है और शिकायतकर्ता से इस बारे में विस्तार से बताने की उम्मीद करना अनुचित होगा। कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि अधिनियम की धारा 141 (1) की भाषा के संदर्भ में एक कथन किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले के तथ्यों में विद्यमान स्थिति में, उच्च न्यायालय को शिकायत को तभी रद्द करना चाहिए था जब संबंधित निदेशक ने स्टर्लिंग साक्ष्य प्रदान किया कि वह वास्तव में कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं था। इस प्रकार, कानून की व्याख्या, कि जिस तरीके से एक व्यक्ति, निदेशक होने के नाते अपने मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार था, के बारे में विवरण को बुरा घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस मामले में, संबंधित निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया था।

18. स्टैंडर्ड चार्टर्ड ***बैंक (सुप्रा)*** *में* आरोपी-कंपनी ने एक बैंक द्वारा दिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए चेक जारी किए, जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को तलब किया जिसे पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी गई थी लेकिन खारिज कर दिया गया था। परिणामस्वरूप उक्त आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। दो आरोपी निदेशकों द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर स्वीकार किया गया कि शिकायत में उक्त निदेशकों की भूमिका के बारे में कोई विशेष दावा नहीं किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि -

i. शिकायत में ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिससे मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का मन बना सके क्योंकि मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है;

ii. अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व केवल तभी उत्पन्न होता है जब यह दिखाया जाता है कि एक आरोपी व्यक्ति प्रासंगिक समय में कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था;

iii. चूंकि दायित्व आरोपी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति के कारण है, इसलिए उसे उत्तरदायी बनाने के लिए उपयुक्त तथ्यों का खुलासा करना आवश्यक है;

iv. प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक या चेक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मामले में, यह कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था; और

v. कंपनी के किसी अन्य अधिकारी को उत्तरदायी बनाने के लिए कंपनी में उसकी भूमिका और कर्तव्य के बारे में विशिष्ट कथन आवश्यक है।

19. इस प्रकार, यह माना गया कि चेकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कंपनी के व्यवसाय के संचालन में उनकी भागीदारी के बारे में किसी भी कथन के अभाव में भी अपराध के लिए उत्तरदायी थे। पूर्णकालिक निदेशक भी उत्तरदायी थे क्योंकि ऐसे निदेशक अपनी क्षमता में वे दैनिक आधार पर भी कंपनी के व्यवसाय के संचालन में शामिल होंगे

[6] 2015(1) आरसीआर (सीआरएल) 54

[7] 2016(2) आरसीआर (सीआरएल) 778

और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 141 की भाषा के संदर्भ में कथन पर्याप्त था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया था। यह निर्णय वर्तमान मामले में मुद्दे पर नहीं है। वास्तव में, इस फैसले में भी, यह दोहराया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक तथ्यों की पैरवी करना आवश्यक है।

20. इस प्रकार, इस विषय पर कानून में कोई अस्पष्टता नहीं है।

21. इस मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने 10.02.2006 से इस्तीफा दे दिया था। विवादित चेक बहुत बाद में जारी किया गया था। फॉर्म नंबर 32 और कंपनी की वार्षिक रिटर्न को रिकॉर्ड पर रखा गया है और इसे अस्वीकार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता पर प्रत्यावर्ती दायित्व लगाने के लिए, कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, कंपनी के व्यवसाय के संचालन में उसकी भूमिका के बारे में शिकायत में विशिष्ट कथन करना आवश्यक था। इस मामले में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता को समन करने में न्यायसंगत नहीं था। किसी अभियुक्त व्यक्ति को तलब करने के चरण में, ट्रायल कोर्ट/मजिस्ट्रेट को उसके समक्ष पेश की गई सामग्री के आधार पर संतुष्ट होना चाहिए कि *प्रथम दृष्टया* आरोपी व्यक्तियों ने अपराध किया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने उत्तर के माध्यम से संदर्भित सामग्री को इस स्तर पर नहीं देखा जा सकता है क्योंकि शिकायत में इसका उल्लेख या भरोसा नहीं किया गया है।

<u>सीआरएम-एम-12745-2018</u>

22. इस मामले को अलग से लिया जा रहा है क्योंकि शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से याचिकाकर्ता कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, उसके बारे में विशिष्ट कथन शिकायत में किए गए हैं।

23. शिकायत अनुबंध पी-1 के रूप में रिकॉर्ड में है। याचिकाकर्ता को आरोपी नंबर 3 के रूप में पेश किया गया है। इसका अवलोकन विद्वान वकील के तर्क का समर्थन नहीं करता है।

24. इस स्थिति का सामना करते हुए, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 138 के तहत जारी नोटिस की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जो रिकॉर्ड पर अनुलग्नक पी -6 है। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त नोटिस शिकायत का एक हिस्सा है और उसमें आवश्यक कथन किए गए हैं। इस प्रकार, बुलाने के क्रम में कोई त्रुटि नहीं है।

25. याचिकाकर्ता नोटिस नंबर 3 है। उनके बारे में किया गया कथन इस प्रकार है:-

"आप पता नंबर 3 अभिभाषक नंबर 1 के अध्यक्ष/निदेशक होने के नाते भी प्रभारी हैं और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए पता नंबर 1 कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते भी अधिनियम के तहत निर्धारित दंड के लिए उत्तरदायी हैं।

26. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस में किए गए कथनों को शिकायत में किए गए कथन के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, यहां तक कि कानूनी नोटिस में किए गए कथन भी कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। इस प्रकार, शिकायतकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क गलत है और खारिज कर दिया गया है।

27. तदनुसार, याचिकाओं की अनुमति दी जाती है; सम्मन आदेशों के साथ-साथ शिकायतें, जो संबंधित याचिकाओं की विषय वस्तु हैं, और परिणामी कार्यवाही जो उससे उत्पन्न हुई हैं, याचिकाकर्ता के लिए रद्द कर दी जाती हैं।

28. इस स्तर पर, सुदीप जैन ***(सुप्रा)*** *मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित होगा।*दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि मुकदमेबाजी को कम करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेटों के लिए यह उचित होगा कि वे फॉर्म नंबर 32 और कंपनी द्वारा दायर नवीनतम वार्षिक रिटर्न की प्रतियां मांगें ताकि केवल उन व्यक्तियों को बुलाया जा सके जो अपराध होने की तारीख को निदेशक हैं।

29. मैं दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि उन सभी मामलों में जहां आरोपी एक 'कंपनी' है, आरोपी व्यक्तियों को समन जारी करने से पहले ट्रायल कोर्ट/मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को फॉर्म नंबर 32 की एक प्रति और कंपनी द्वारा दायर वार्षिक रिटर्न पेश करने का निर्देश देगा ताकि उन व्यक्तियों का निर्धारण किया जा सके, जो अपराध होने की तारीख को निदेशक थे। ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त-निदेशक अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक या चेक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं, उन्हें कंपनी के मामलों के संचालन

में उनकी भूमिका के बारे में बिना किसी कथन के बुलाया जा सकता है। कंपनी के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी को बुलाने के लिए कंपनी के कारोबार के संचालन में उनकी भूमिका के बारे में आवश्यक कथन पर जोर दिया जाना चाहिए। पूर्णकालिक निदेशकों के संबंध में, अधिनियम की धारा 141 के शब्दों को केवल पुन: प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

30. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों के सभी जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के जिला न्यायाधीश को भेजी जाए।

शुबरीत कौर

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी